IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड–19 का प्रभाव – चुनौतियाँ एवं समस्या समाधान के संभावित उपाय

डॉ. सौरभ कुमार झा

अतिथि सहायक प्रध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग यू0आर0 कॉलेज, रोसड़ा

ललित नारायण मिथिला वि0वि0, दरभंगा

सारः कोविड–19 महामारी ने विश्व स्तर पर एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट खड़ा कर दिया जिससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा और भारत इसका अपवाद नहीं रहा है। इस शोध लेख का उद्देश्य महामारी के परिणामस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली बहुमुखी चुनौतियों का विश्लेषण करना और इसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए संभावित समाधान प्रस्तावित करना है। निष्कर्ष में भारत में कोविड–19 के आर्थिक नतीजों को संबोधित करने के लिए सक्रिय उपायों और नीतिगत हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया गया हैं। विश्लेषण से पता चलता है कि महामारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण व्यवधान पैदा किया। आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान, उपभोक्ता मांग में कमी और श्रम बाजार की चुनौतियों के कारण विनिर्माण, सेवाओं, पर्यटन और कृषि सभी को बड़े झटके लगे। इन व्यवधानों के कारण बेरोजगारी दर में वृद्धि हुई और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में गिरावट आई। राजकोषीय घाटे तथा व्यापार और निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव ने आर्थिक चुनौतियों को और बढ़ा दिया। इन मुद्दों को हल करने के लिए, आलेख में संभावित समाधानों और नीतिगत हस्तक्षेपों को प्रस्तावित किया गया है।

मुख्य शब्दः कोविड–19, लॉकडाउन, अर्थव्यवस्था, राजकोषीय घाटा, सकल घरेलू उत्पाद, आपूर्ति श्रृंखला

परिचय

2020 की शुरुआत में कोविड–19 महामारी के प्रकोप ने वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को बाधित कर दिया जिससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा और भारत ने भी महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव देखा। कोविड–19 महामारी से वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं सहित भारत में व्यवधान और अभूतपूर्व चुनौतियाँ पैदा हुई हैं। भारत, अपनी विशाल आबादी और विविध आर्थिक क्षेत्रों के साथ, महामारी से काफी प्रभावित हुआ है। इस शोध लेख का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड–19 के प्रभाव का व्यापक विश्लेषण प्रदान करना है, सामना की गई चुनौतियों पर प्रकाश डालना और इसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए संभावित समाधान प्रस्तावित करना है।

कोविड–19 का प्रकोप, जो 2020 की शुरुआत में उभरा, तेजी से वैश्विक स्वास्थ्य संकट में बदल गया। भारत, अपने घनी आबादी वाले शहरों और उच्च गतिशीलता के साथ, वायरस के प्रसार को रोकने में भारी चुनौतियों का सामना किया। सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सख्त लॉकडाउन उपाय लागू किए, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक क्षेत्रों में व्यापक व्यवधान हुआ।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड–19 का प्रभाव व्यापक और दूरगामी रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो कि भारत की जीडीपी में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है, ने आवागमन पर प्रतिबंध और कार्यबल की उपलब्धता में कमी के कारण आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान का अनुभव किया। नतीजतन, औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में भारी गिरावट देखी गई। गतिशीलता पर लगाए गए प्रतिबंधों और उपभोक्ता खर्च में गिरावट से आतिथ्य, परिवहन और खुदरा सहित सेवा क्षेत्र गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था। पर्यटन उद्योग, राजस्व और रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत, यात्रा प्रतिबंधों और सुरक्षा चिंताओं के कारण रद्दीकरण और बंद होने के कारण निकट ठहराव का सामना करना पड़ा। इसके अलावा, कृषि क्षेत्र, जो आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को रोजगार देता है, को श्रम की कमी और बाधित आपूर्ति श्रृंखलाओं का सामना करना पड़ा, जिससे उत्पादन और आय दोनों प्रभावित हुए।

सामना की गई चुनौतियों के परिमाण को समझने के लिए, डेटा और आँकड़े मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार, वित्त वर्ष 2020–21 (अप्रैल से मार्च) में भारत की जीडीपी में 7. 3 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो दशकों में सबसे तेज गिरावट है। विश्व बैंक का अनुमान लगाया कि महामारी अतिरिक्त 12 मिलियन भारतीयों को गरीबी में धकेल सकती है। अप्रैल 2020 में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी में 23.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ बेरोजगारी दर रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई।

करों में कमी तथा राजस्व और स्वास्थ्य देखभाल और राहत उपायों पर सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण राजकोषीय घाटा बढ़ गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए जीडीपी के 9.5 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह और निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) के अनुसार, भारत ने 2020 में एफडीआई प्रवाह में 27 प्रतिशत की गिरावट का अनुभव किया।

महामारी से उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों पर तत्काल ध्यान देने और रणनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। नीति निर्माताओं और हितधारकों को दीर्घकालिक प्रभाव को कम करने और एक मजबूत वसूली की सुविधा के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। विभिन्न समाधान और नीतिगत हस्तक्षेप भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में मदद कर सकते हैं।

राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने और उपभोक्ता विश्वास बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सरकार ने कई राहत उपायों को लागू किया है, जिसमें समाज के कमजोर वर्गों को आय समर्थन, एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों) के लिए ऋण गारंटी और वित्तीय प्रणाली में तरलता शामिल हैं। इन उपायों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को स्थिर करना, व्यवसायों का समर्थन करना और नौकरियों की रक्षा करना है। इसके अलावा, रोजगार सृजन योजनाएं और कौशल विकास कार्यक्रम बढ़ती बेरोजगारी दर को कम करने में मदद कर सकते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) और स्किल इंडिया मिशन जैसी पहलें आजीविका के अवसर प्रदान कर सकती हैं और कार्यबल की रोजगार क्षमता को बढ़ा सकती हैं। छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए समर्थन महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ऋण अधिस्थगन, ब्याज दर में कटौती और सरलीकृत नियामक प्रक्रियाओं जैसे उपाय वित्तीय बोझ को कम कर सकते हैं और व्यापार निरंतरता को बढ़ावा दे सकते हैं। साथ ही डिजिटल परिवर्तन आर्थिक सुधार के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम कर सकता है। ई–कॉमर्स, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ावा देने से व्यवसायों को नए सामान्य के अनुकूल होने और ग्राहकों तक संपर्क रहित तरीके से पहुंचने में मदद मिल सकती है।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड 19 का प्रभाव

कोविड –19 महामारी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में व्यवधान और चुनौतियाँ पैदा हुई हैं। कोविड –19 के प्रसार को रोकने के लिए लागू किए गए कड़े उपायों के परिणामस्वरूप देश के आर्थिक परिदृश्य में काफी बदलाव आया है।

1. जीडीपी वृद्धिः महामारी के कारण भारत की जीडीपी वृद्धि दर में महत्वपूर्ण संकुचन देखा गया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार, वित्त वर्ष 2020–21 (अप्रैल से मार्च) में भारत की जीडीपी में 7.3 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो दशकों में सबसे तेज गिरावट है। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020 के लिए भारत की जीडीपी में 9.6 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 8 प्रतिशत के संकुचन का अनुमान लगाया। आर्थिक विकास में इस गिरावट का देश के विकास और समृद्धि पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है।

2. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टरः मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देता है, को काफी बाधाओं का सामना करना पड़ा। लॉकडाउन और आवाजही पर प्रतिबंध के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, श्रम की कमी और उत्पादन में कमी आई। मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) अप्रैल 2020 में 27.4 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गया। ऑटोमोबाइल, कपड़ा और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उद्योगों के उत्पादन और निर्यात में भारी गिरावट आई।

3. सेवा क्षेत्रः आतिथ्य, पर्यटन, परिवहन और खुदरा सहित सेवा क्षेत्र, जो भारत की जीडीपी और रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान देता है, महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुआ। यात्रा प्रतिबंधों, सामाजिक दूरी के उपाय और लॉकडाउन के कारण आतिथ्य और विमानन सहित यात्रा और पर्यटन उद्योग को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। होटल, रेस्तरां और विमानन कंपनियों को भारी राजस्व नुकसान और नौकरी में कटौती का सामना करना पड़ा। 2020 में घरेलू हवाई यात्री यातायात में 39.4 प्रतिशत की गिरावट के साथ, इस क्षेत्र ने राजस्व में भारी गिरावट का अनुभव किया।

4. बेरोजगारी और आय का नुकसानः महामारी के परिणामस्वरूप बेरोजगारी दर और आय में काफी कमी आई। सख्त लॉकडाउन उपायों के परिणामस्वरूप व्यवसाय बंद हो गए और आर्थिक गतिविधियां ठप हो गईं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) ने अप्रैल 2020 में 23.5 प्रतिशत की बेरोजगारी दर की सूचना दी। अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक, दैनिक वेतन भोगी और प्रवासी श्रमिक विशेष रूप से प्रभावित हुए, जो नौकरी के नुकसान और आय के अवसरों में कमी का सामना कर रहे थे।

5. राजकोषीय घाटा और सरकारी ऋणः कोविड–19 के कारण उत्पन्न स्वास्थ्य और आर्थिक संकट से निपटने के लिए, भारत सरकार ने अपने खर्च में वृद्धि की, जिससे राजकोषीय घाटे में वृद्धि हुई और साथ ही सरकारी ऋण में भी वृद्धि हुई। कर राजस्व में कमी के साथ–साथ स्वास्थ्य सेवा, राहत उपायों और प्रोत्साहन पैकेजों पर बढ़े हुए खर्च ने देश की राजकोषीय स्थिति को प्रभावित किया। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए राजकोषीय घाटा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सकल घरेलू उत्पाद का 9.5 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया था।

6. व्यापार और निवेशः महामारी का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेशी निवेश पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान, घटी हुई मांग और यात्रा प्रतिबंधों ने निर्यात और आयात को बाधित किया। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह में गिरावट आई, जिससे निवेश की संभावनाएं और आर्थिक विकास प्रभावित हुआ। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने 2020 के लिए भारत के व्यापारिक निर्यात में 9.2 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह में भी गिरावट देखी गई। वित्तीय वर्ष 2020–21 में, FDI प्रवाह 19 प्रतिशत घटकर +59.64 बिलियन हो गया।

7. कृषि क्षेत्रः कृषि क्षेत्र, जबकि अन्य क्षेत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक लचीला है, को महामारी के दौरान चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भारतीय आबादी के एक बड़े हिस्से को रोजगार देने वाले कृषि क्षेत्र को महामारी के दौरान चुनौतियों का सामना करना पड़ा। प्रवासन और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और श्रम की कमी ने कृषि गतिविधियों को प्रभावित किया जिससे कृषि उत्पादन में बाधा उत्पन्न हुई। इससे किसानों की आय प्रभावित हुई जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। वित्तीय वर्ष 2020–21 में कृषि सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ इस क्षेत्र की वृद्धि में गिरावट देखी गई, जबकि पिछले वर्ष में यह 4.3 प्रतिशत थी।

कोविड–19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियाँ

कोविड–19 महामारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश की हैं। महामारी के परिणामस्वरूप भारत के सामने कुछ प्रमुख चुनौतियाँ निम्न हैं:

1. आर्थिक संकुचनः महामारी ने भारत में एक गंभीर आर्थिक संकुचन का कारण बना, जिससे आर्थिक विकास में तेज गिरावट आई। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और आंदोलन पर प्रतिबंध ने विनिर्माण, निर्माण और सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों को बाधित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप नौकरी छूट गई, उपभोक्ता खर्च में कमी आई और निवेश में कमी आई।

2. बेरोजगारी और नौकरी का नुकसानः महामारी के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर नौकरी का नुकसान और बेरोजगारी हुई। कई व्यवसायों, विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) को अपने संचालन को बंद करने या कम करने के लिए मजबूर किया गया, जिससे लाखों श्रमिकों की छंटनी और आय का नुकसान हुआ। अनौपचारिक क्षेत्र, जो आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को रोजगार देता है, विशेष रूप से प्रभावित हुआ।

3. आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधानः महामारी के कारण होने वाले व्यवधानों, जिसमें आवाजाही और परिवहन पर प्रतिबंध शामिल हैं, ने आपूर्ति श्रृंखलाओं में महत्वपूर्ण व्यवधान पैदा किए। आयातित निविष्टियों पर निर्भर उद्योगों को वैश्विक व्यापार में व्यवधान और आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे उत्पादन प्रभावित हुआ और लागत में वृद्धि हुई।

4. उपभोक्ता मांग में गिरावटः महामारी के दौरान उपभोक्ता मांग में भारी गिरावट देखी गई। आय के स्तर में कमी, नौकरी की अनिश्चितता और एहतियाती बचत के कारण खुदरा, आतिथ्य और पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में उपभोक्ता खर्च में कमी आई है। इसका व्यवसायों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और इसके परिणामस्वरूप उत्पादन और नौकरी के नुकसान में कमी आई।

5. वित्तीय तनावः कई व्यवसायों, विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को राजस्व कम होने और संचालन बाधित होने के कारण वित्तीय तनाव का सामना करना पड़ा। नकदी प्रवाह की समस्याएं, ऋण प्राप्त करने में कठिनाई, और बढ़ते कर्ज के बोझ ने उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां खड़ी कर दीं और उनकी वसूली की क्षमता में बाधा उत्पन्न की।

6. अनौपचारिक क्षेत्र की चुनौतियाँ: अनौपचारिक क्षेत्र, जिसमें भारत के कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा शामिल है, को महामारी के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सामाजिक सुरक्षा लाभों की कमी, स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुंच और अपर्याप्त सरकारी सहायता ने अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों के सामने आने वाली कठिनाइयों को जोड़ा।

7. हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर: महामारी ने भारत के हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरियों को उजागर किया। कोविड–19 मामलों में अचानक वृद्धि ने अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं को चरमरा दिया, जिससे बिस्तरों, चिकित्सा उपकरणों और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी हो गई। स्वास्थ्य संकट के प्रबंधन के लिए संसाधन आवंटित करने की आवश्यकता ने समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को प्रभावित किया।

8. राजकोषीय बाधाएं: अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रभाव के साथ–साथ सरकार द्वारा राहत उपाय प्रदान करने और वसूली में सहायता देने के प्रयासों के कारण राजकोषीय बाधाएं उत्पन्न हुईं। स्वास्थ्य देखभाल खर्च में वृद्धि, कर राजस्व में कमी, और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त व्यय ने सरकार के वित्त पर दबाव डाला है, जिससे दीर्घकालिक निवेश और सुधार करने की इसकी क्षमता प्रभावित हुई है।

9. बढ़ती असमानता: महामारी ने भारत में मौजूदा सामाजिक–आर्थिक असमानताओं को बढ़ा दिया है। प्रवासी श्रमिकों, दैनिक वेतन भोगियों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों सहित समाज के कमजोर वर्गों को विषम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दूरस्थ कार्य के रूप में डिजिटल विभाजन और गहरा गया और ऑनलाइन शिक्षा आदर्श बन गई, जिससे प्रौद्योगिकी और डिजिटल संसाधनों तक पहुंच कई लोगों के लिए एक चुनौती बन गई।

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए बहु–आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय, लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप, स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे में निवेश, व्यवसायों के लिए समर्थन, रोजगार सृजन और समाज के कमजोर वर्गों पर प्रभाव को कम करने के लिए सामाजिक कल्याण के उपाय शामिल हैं।

वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्या के समाधान के संभावित उपाय

कोविड–19 महामारी के कारण वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए, प्रभाव को कम करने और आर्थिक सुधार का समर्थन करने के कुछ संभावित उपाय निम्न हैं:

- महामारी से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्तियों के लिए लक्षित वित्तीय सहायता उपायों को लागू किया जाना चाहिए। प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान किया जाना चाहिए। ऋण स्थगन का विस्तार किया जाना चाहिए और व्यवसायों, विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) को ऋण गारंटी प्रदान किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सहायता सबसे कमजोर आबादी तक पहुंचे, जैसे कि प्रवासी श्रमिक और दैनिक वेतन भोगी।
- उपभोक्ता मांग और खर्च को प्रोत्साहित करने के उपायों को लागू किया जाना चाहिए। इसमें करों में अस्थायी कटौती, उपभोक्ता खर्च के लिए प्रोत्साहन और खुदरा, आतिथ्य और पर्यटन जैसे क्षेत्रों के लिए समर्थन शामिल हो सकता है। यात्रा और आतिथ्य उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- हेल्थकेयर, ट्रांसपोर्टेशन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और निवेश में तेजी लाया जाना चाहिए। इससे रोजगार सृजित होंगे, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और देश के दीर्घकालिक विकास की संभावनाओं में वृद्धि होगी। उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए जो रोजगार पैदा करती हैं और अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव डालती हैं।
- बदलते आर्थिक परिदृश्य के अनुकूल होने के लिए सभी क्षेत्रों में डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ई–कॉमर्स, ऑनलाइन शिक्षा और दूरस्थ कार्य को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया जाना चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाया जाना चाहिए और सभी के लिए समावेश और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।
- भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के प्रयास जारी रखा जाना चाहिए। नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाना चाहिए, नौकरशाही को कम किया जाना चाहिए और अनावश्यक प्रशासनिक बोझ को खत्म किया जाना चाहिए। उद्यमिता और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवसायों, विशेष रूप से स्टार्टअप और एसएमई के लिए तेजी से अनुमोदन और परमिट की सुविधा प्रदान करना चाहिए।
- रोज़गार क्षमता बढ़ाने के लिए रीस्किलिंग और अपस्किलिंग कार्यक्रमों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। नौकरी के उभरते अवसरों के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने के लिए उद्योग भागीदारों के साथ सहयोग किया जाना चाहिए। सहायक नीतियों और प्रोत्साहनों के माध्यम से उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- अस्पताल सुविधाओं के विस्तार, चिकित्सा उपकरणों की खरीद और हेल्थकेयर पेशेवरों के प्रशिक्षण सहित हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया जाना चाहिए। विशेष रूप से ग्रामीण और कम सेवा वाले क्षेत्रों में

गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना चाहिए। एक मजबूत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का निर्माण करके भविष्य के स्वास्थ्य संकटों के लिए तैयार रहना चाहिए।

- सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, वित्तीय सहायता प्राप्त करने और व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों और संगठनों के साथ सहयोग किया जाना चाहिए। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ाने के लिए साझेदारी को बढ़ावा देना चाहिए। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अवसरों की तलाश करें और भारतीय व्यवसायों के लिए बाजार पहुंच का विस्तार किया जाना चाहिए।
- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि रिकवरी प्रक्रिया टिकाऊ और समावेशी हो। पर्यावरणीय स्थिरता पर ध्यान दिया जाना चाहिए और हरित पहलों को अपनाया जाना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा उपायों को लागू करना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करना चाहिए और वंचित समुदायों को सहायता प्रदान करना चाहिए। लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और कमजोर आबादी की जरूरतों को प्राथमिकता देना चाहिए।
- आय असमानता को कम करने और समाज के सभी वर्गों के लिए आवश्यक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए समावेशी विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम लागू किए जाने चाहिए। सतत प्रथाओं, नवीकरणीय ऊर्जा और संसाधन प्रबंधन की ओर निर्देशित प्रयासों के साथ पर्यावरणीय स्थिरता एक प्राथमिकता होनी चाहिए।
- एक स्थिर आर्थिक वातावरण बनाए रखने के लिए राजकोषीय अनुशासन और प्रभावी सार्वजनिक ऋण प्रबंधन सुनिश्चित करना आवश्यक है। शासन और प्रशासनिक सुधारों को व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर ध्यान देना चाहिए।
- नीति निर्माताओं, हितधारकों और समग्र रूप से समाज के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे कार्यान्वित उपायों की प्रगति की निरंतर निगरानी करें, आवश्यक समायोजन करें और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल रहें।

उभरती हुई स्थिति की निरंतर निगरानी करना, आवश्यकतानुसार नीतियों को अनुकूलित करना और वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने और आर्थिक सुधार का समर्थन करने के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इन उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने में सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों के बीच सहयोग आवश्यक होगा।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि कोविड–19 महामारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश की हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। देश ने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि, विनिर्माण उत्पादन, रोजगार दर और विदेशी निवेश में गिरावट का सामना किया है। इसके अतिरिक्त, बेरोजगारी, गरीबी, अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे और राजकोषीय घाटे जैसी पहले से मौजूद चुनौतियाँ और अधिक तीव्र हो गई हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण और लक्षित समाधानों के कार्यान्वयन की आवश्यकता है। उत्पादकता और ग्रामीण आजीविका में सुधार के लिए सरकार को रोजगार सृजन, कौशल विकास और कृषि क्षेत्र में सुधार को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और आर्थिक विकास को सुगम बनाने के लिए परिवहन और ऊर्जा सहित बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश महत्वपूर्ण हैं।

संदर्भ

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, भारत सरकार। (2021)। एफडीआई सांख्यिकी। Retrieved from https://dipp.gov.in/

नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार (2021). वार्षिक रिपोर्ट 2020–21। Retrieved from https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/Annual_Report-2020-21.pdf

भारतीय रिजर्व बैंक (2020). भारतीय अर्थव्यवस्था 2019–20 पर सांख्यिकी की पुस्तिका। Retrieved from https://www.rbi.org.in/Scripts/AnnualPublications.aspx?head=Handbook%20of%20Statistics%20on%20Indian%20Economy

भारतीय रिजर्व बैंक (2021). प्रेस विज्ञप्तिः विकासात्मक और नियामक नीतियों पर वक्तव्य। Retrieved from https://www.rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=52699

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (2020). आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), 2019–20 पर वार्षिक रिपोर्ट। Retrieved from http://www.mospi.gov.in/sites/default/files/press_release/Labour_Report_2019_20.pdf

विश्व व्यापार संगठन (2020). वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2020. Retrieved from https://www.wto.org/

विश्व बैंक (2021). गरीबी और साझा समृद्धि 2021 पर रिर्पोट।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (2021). वार्षिक राष्ट्रीय आय, 2020–21 के अनंतिम अनुमानों और सकल घरेलू उत्पाद के तिमाही अनुमान, Q4, 2020-21. Retrieved from https://www.mospi.gov.in/sites/default/files/press_release/PRESS_NOTE_Press_Release_2020-21.pdf

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) (2020). सीएमआईई बेरोजगारी डेटाबेस। Retrieved from https://www.cmie.com/